डिजीटल पत्र
दैनिक
कांग्रेस दर्पण
पटना, 18 जुलाई, गुरुवार, 2024
बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल सदाकत आश्रम पटना - 10

सुस्त निवेश से 10 वर्ष में घटी आर्थिक विकास की रफ्तार

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली : कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार भले ही बराबर तेज आर्थिक विकास की बात करती है लेकिन सच यही है कि पिछले 10 वर्ष के दौरान विदेशी निवेश में कमी आई है और इसके कारण आर्थिक विकास की रफ्तार कमजोर पड़ी है.

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने आज यहां कहा,''2014 के बाद से भारत के तेज़ी से वृद्धि न करने का मुख्य कारण सुस्त निवेश दर, अस्थिर नीतियां, मित्र पूंजीवाद का बोलबाला के साथ ही ईडी, आईटी, सीबीआई का रेड- इन तीन वजहों से 2014 से कम निवेश हो रहा है. उन्होंने कहा, कम निवेश मध्यम और दीर्घकालिक जीडीपी की वृद्धि दर को नीचे खींचता है, जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी और

उपभोग वृद्धि में गिरावट आती है. भारत में निजी घरेलू निवेश 2014 से सुस्त है. डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान यह जीडीपी के 25-30 प्रतिशत के रेंज में था. स्वयंभू परमात्मा के अवतार के कार्यकाल में, यह जीडीपी के 20-25 प्रतिशत के रेंज में है लेकिन 2014 से सकल एफडीआई भी कमोबेश स्थिर रहा है. हालांकि, यह कहानी का केवल एक हिस्सा भर है. कम से कम 2016 से, दुनिया भर की बहु-राष्ट्रीय कंपनियाँ चीन से हटकर अन्य विकासशील देशों में निवेश करना चाह रही हैं.

कांग्रेस सेवा दल की सदस्यता ग्रहण कर सेवा निवृत्त होकर बाकी जीवन समाज सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

बिहार प्रदेश कॉंग्रेस सेवादल द्वारा चलाई जा रही सदस्यता अभियान कार्यक्रम में आदरणीय कार्यकारी मुख्य संगठक डॉ प्रोफेसर संजय कुमार यादव के अध्यक्षता में मनेर के रहने वाले सेवानिवृत्त इंजिनियर सुभाष सिंह और एक्स आर्मी सुबोध कुमार चौधरी ने सदाकत आश्रम में सदस्यता ग्रहण किए और सेवा निवृत्त होकर बाकी जिवन समाज सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। जहां विशिष्ट अतिथि कॉंग्रेस के पुर्व एमएलसी लाल बाबू लाल,वार-रुम के उपाध्यक्ष राज छवि राज, कोषाध्यक्ष - आशुतोष रंजन, प्रदेश महासचिव - सुनील कुमार सुमन, कार्यालय प्रभारी बिपिन झा, पटना व वैशाली जिला प्रभारी सुकेश कुमार, स्वयं सेवक एक्स आर्मी राकेश पाठक, सुदेश शर्मा, रमन वर्मा व अन्य लोग उपस्थित थे। बिहार प्रदेश कॉंग्रेस सेवादल परिवार दोनों नए साथियों का स्वागत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

दिग्विजय सिंह ने की आएसएस की तारीफ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कही ये बात

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सिविक सेंटर में चल रहे युवा कांग्रेस के धरने में पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो आरएसएस से सीखो, जो कि हमारे मुख्य विरोधी हैं, लेकिन वो माइंड गेम खेलते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस ना कभी आंदोलन करेंगे, ना कभी प्रदर्शन करेंगे, ना कभी डंडे खाएंगे और ना ही कभी जेल जाएंगे लेकिन हम लोग को जरूर जेल भिजवांएगे। इसलिए उनसे कुछ सीखते हुए संकल्प लेना चाहिए। इतना सुनते ही धरना समाप्त कर दिया।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि संस्कारधानी में 20 जुलाई को हो रही रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, पर इसकी हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट महज सात ही है। प्रदेश में आज इन्वेस्टर सबमिट सिर्फ फोन एक्सचेंज करना और भाईचारा स्थापित करने तक ही सीमित रह गई हैं। जबलपुर में होने वाली इंवेस्टरमीट का भी यही हाल होगा। इस मीट के दौरान बड़े-बड़े अधिकारी और निवेशक, उद्योगपति आपस में अपने संबंधों को मजबूत करते हैं लेकिन इसमें उद्यमियों का कुछ नहीं होता है और ना ही प्रदेश के युवकों को रोजगार मिलता है।

जबलपुर में लगाए जा रहे स्मार्टमीटर के पीछे चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने नगर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को सराहा और कहा कि मोंटी कार्लो कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो मुख्यतौर पर गुजरात की है। ये कंपनी खुद काम करने की बजाए पेटी पर काम दे रही है, जिससे मीटर की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में चल रहे पौधारोपण में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार पेड़ कटवा रही है तो दूसरी तरफ पौधारोपण जैसे कार्यक्रम कर रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार का पौधारोपण अभियान रिकॉर्ड बनाने के होता हैं। जबकि आज पौधे लगवाना, गड्ढे करवाना और फिर भ्रष्टाचार करना ही इस अभियान का काम रह गया है। 20 रुपए का गड्ढा और 30 रुपए का पौधा। अनुमानित एक पौधा लगाने में 50 रुपये मध्यप्रदेश सरकार खर्च कर रही है, जिससे यह समझा जा सकता है कि प्रदेशभर में पौधारोपण के नाम पर कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जन सेवा नहीं बल्कि धन सेवा के लिए आती है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से की मुलाकात

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की।

केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट किया, ''हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।''

दिल्ली दौरे पर आये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पानी और पर्यटन पर निवेश के लिए केंद्र सरकार से मदद के लिए आग्रह किया। इसके साथ ही आगामी बजट में हिमाचल प्रदेश का विशेष ध्यान रखने के लिए भी निवेदन किया।

कोरोना जैसी महामारी से इस सरकार ने कुछ नहीं सीखा

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

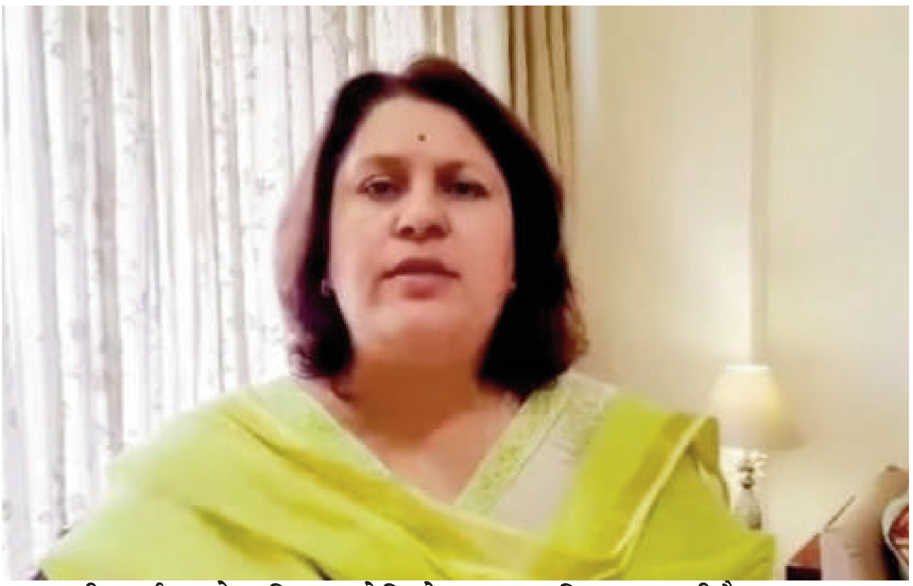

यह ख़बर शायद आपकी नज़रों से बच गई हो कि वर्ष 2023 में हमारे देश के 16 लाख बच्चों को किसी प्रकार का कोई टीका ही नहीं लगा. जिनमें पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, चेचक, और हेपटाइटिस जैसे अनेक टीके शामिल हैं. UNICEF की ये रिपोर्ट भयावह है.

भारत में प्रतिवर्ष क़रीब 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और सामान्यतः एक बच्चे को जन्म से 1 वर्ष की आयु होने तक 9 से 10 तरह के टीके लगते हैं. अगर सिर्फ़ 1 वर्ष में 16 लाख बच्चे टीकों से वंचित रह जाते हैं तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मोदी सरकार की यह विफलता कुछ ही सालों में कितनी बड़ी महामारी का रूप ले लेगी.

आज़ादी के बाद से कांग्रेस सरकार ने मुफ़्त टीकाकरण पर ज़ोर दिया और डॉ॰ मनमोहन सिंह की UPA सरकार में NRHM (National Rural Health Mission) के ज़रिए गाँव-गाँव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर टीकाकरण एक बेहद सफल कार्यक्रम रहा. इसी कार्यक्रम के ज़रिए हम पोलियो मुक्त देश बन पाए. लेकिन UNICEF के आँकड़े देख कर डर लगता है कि हमारे देश में पोलियो और चेचक जैसे रोग फिर से वापस न आ जाएँ.

दूसरी बात यह कि एक नवजात का टीकाकरण उतना ही अनिवार्य है जितना कि उसके पैदा होने पर साँस लेना और रोना शुरू करना. यह किसी भी सरकार का दायित्व है कि देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे का 'मुफ़्त टीकाकरण' सुनिश्चित करे. लेकिन यह सरकार तो काम करने में कम और ढिंढोरा पीटने में ज़्यादा विश्वास रखती है.

हमारे देश में हमेशा से आवश्यक टीके मुफ़्त रहे हैं लेकिन इसका कभी ढिंढोरा नहीं पीटा गया और न ही इस पर राजनीति खेली गई. लेकिन कोविड के दौरान जिस तरह से टीकों के नाम वोट माँगने की राजनीति की गई और जनता पर एहसान जताया गया, वो साबित करता है कि इन्हें चिन्ता आपके स्वास्थ्य की नहीं, अपने वोट की है.

विश्वगुरु होने का दम्भ भरने वाला यह देश Zero Dose Children के मामले में दूसरे नम्बर का देश बन गया है, पहले नम्बर पर नाइजीरिया है और यह दिखाता है कि-

-कोरोना जैसी महामारी से इस सरकार ने कुछ नहीं सीखा

-स्वास्थ्य सेवाओं की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है

-ग़रीब जनता के लिए सस्ता इलाज तो दूर की बार, प्राण रक्षक टीके भी मुश्किल हो गए हैं

-नरेंद्र मोदी ने अपने दो कार्यकाल में सिवाय फ़ोटो खिंचाने और बड़े-बड़े विज्ञापनों के अलावा कुछ नहीं किया

-तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार बचाने और अंतर्कलह सुलझाने में व्यस्त हैं, स्वास्थ्य जैसा अहम मुद्दा दूर-दूर तक उनके एजेंडा में ही नहीं है

तो अब आपके बच्चों के स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचने की ज़िम्मेदारी भी आप ही के हाथ में है – सरकार का कोई लेना देना नहीं है

तिलक नगर जिला महिला कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक !

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

आधी आबादी को पूरा हक़ मिले, वह सशक्त हों यह कांग्रेस के एजेंडे का हमेशा से अभिन्न हिस्सा रहा है साथ ही कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

महिला कांग्रेस की बैठक में सभी महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को दिल्ली में हर बूथ पर मज़बूत बनाने का संकल्प लिया।

इस दौरान तिलक नगर प्रेक्षक गीता यादव जी, सहित महिला कांग्रेस पदाधिकारी-कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में दायर की याचिका

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

भोपाल

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। चुनाव में वह भाजपा के रोडमल नागर से 1,46,089 मतों के अंतर से हार गए थे।

दिग्विजय सिंह के कार्यालय ने आईएएनएस को बताया कि अपनी याचिका में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अनियमितताओं को उजागर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव मानदंडों का पालन नहीं किया गया।

प्रचार के दौरान, सिंह ने लोगों से यह कहते हुए समर्थन मांगा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है।सिंह ने पहले

रिटर्निंग अधिकारी पर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था।

चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कम से कम तीन से पांच लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद थी। इसमें राजगढ़ और छिंदवाड़ा की सीटी भी शामिल थी। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा ने राज्य की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की।

नियम पालन न करने का लगाया आरोप

दिग्विजय सिंह के कार्यालय ने आईएएनएस को बताया कि अपनी याचिका में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने अनियमितताओं को उजागर किया. इसमें आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव मापदंडों का पालन नहीं किया गया. प्रचार के दौरान सिंह ने लोगों से यह कहते हुए समर्थन मांगा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है.

कांग्रेस जीत सकती थी कई सीटें- दिग्विजय सिंह

सिंह ने अपनी याचिका में पहले रिटर्निंग अधिकारी पर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था. चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कम से कम तीन से पांच लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद थी. इसमें राजगढ़ और छिंदवाड़ा की सीटी भी शामिल थी. लेकिन, प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली. भाजपा ने राज्य की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की.

मोहर्रम स्वागत शिविर लगाया गया

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

रांची विधानसभा युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल रहमान के अध्यक्षता में मोहर्रम स्वागत शिविर लगाया गया।आने वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से सभी 18 धारी का खलीफा को तागड़ी तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव राजेश सिन्हा सनी , झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष निशा भगत , khushboo nayak जी, ज़िला उपाध्यक्ष इनायतुल्लाह , नीतीश सिंह , विशाल ठाकुर, सगीर अहमद, मोहसिन अहमद, इमरान , हसन, सूफियान, आशिफ , फ़राज़, अन्य उपस्थित थे

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार, मुख्यमंत्री जी उधार के आइडिया पर श्रेय लेना अच्छी बात नहीं: पटवारी

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ ही मध्य प्रदेश स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी कर सकेंगे। इस विस्तार की जानकारी मुख्य मंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद अपने शोसल मीडिया साइट के माध्य से दी। जिस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए एक्स के माध्यम से कहा है कि मुख्यमंत्री जी, उधार के आइडिया पर श्रेय लेना अच्छी बात नहीं, आपने कोई महान काम नहीं किया है। पूर्व से चली आ रही एक योजना को तुलनात्मक रूप से ज्यादा खराब ढंग से सिर्फ लागू ही किया है।

पहले उनकी प्राथमिक परेशानियों को करें दूर

जीतू पटवारी ने आगे लिखा यदि भाजपा सरकार ईमानदारी से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की समस्या को सुनना, समझना और समाधान करना चाहती है, तो पहले उनकी प्राथमिक परेशानियों को दूर करे। मैं आपके संज्ञान में बहुत ही बुनियादी मुद्दे ला रहा हूं यह अपेक्षा भी कर रहा हूं कि सरकार पहले ऐसी सभी समस्याओं को सूचीबद्ध करे और फिर समाधान का सार्वजनिक वादा करे।

पटवारी ने बताए बुजुर्गों की 10 समस्याएं

1. स्वास्थ्य सेवाएं : मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है. सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की सबसे ज्यादा कमी है और निजी अस्पतालों में इलाज महंगा है!

2. वृद्धाश्रम की कमी : भावनात्मक दृष्टिकोण से वैसे तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए! लेकिन, निराश्रित बुजुर्गों के लिए अभी भी पर्याप्त संख्या में वृद्धाश्रम नहीं हैं! जो हैं, वे अक्सर अत्यधिक भीड़भाड़ वाले होते हैं!

3.आर्थिक असुरक्षा : पेंशन योजनाओं की अपर्याप्तता और आर्थिक सहायता के अभाव में वृद्ध लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं! सरकार को व्यापक सर्वे करवा कर इस जमीनी हकीकत को स्वीकार करना चाहिए!

4. परिवहन की समस्या : सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, जिससे वृद्ध लोगों को कहीं आने-जाने में कठिनाई होती है! प्रदेश के ग्रामीण इलाकों कि यदि गहराई से पड़ताल की जाए, तो आंखें खोलने वाला खुलासा सामने आ सकता है!

5. मानसिक स्वास्थ्य : मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों में भी अकेलापन और सामाजिक अलगाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं! सरकार ने एक आनंद मंत्रालय बनवाया था, वह कहां है?

6. देखभाल की कमी : बहुत से वृद्ध लोगों को परिवार के सदस्यों या पेशेवर देखभालकर्ताओं की पर्याप्त देखभाल नहीं मिल पाती! सरकार एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे और ऐसे सभी बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करे!

7. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी : बहुत से वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं और उनके लाभ की जानकारी नहीं होती! इससे भी वे धोखाधड़ी का शिकार होते हैं! बेहतर होगा सरकार एक वृहद जागरूकता अभियान शुरू करे!

8. भ्रष्टाचार : कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, जिससे वास्तविक लाभार्थियों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पातीं! सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही विधायकों से इसका फीडबैक ले सकती है!

9. सुरक्षा : वृद्ध लोगों के खिलाफ बढ़ते अपराध, जैसे धोखाधड़ी, चोरी और हिंसा, उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं! क्या गृहमंत्री के रूप में आप यह वचन दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित रहेंगे?

10. आवास की समस्या : कई वरिष्ठ नागरिकों के पास स्थायी आवास नहीं होता, जिससे वे असुरक्षित और अस्थिर महसूस करते हैं! सरकार को ऐसे बुजुर्गों को चिन्हित करना चाहिए और उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना चाहिए!

पड़ताल करेंगे तो ऐसी सैकड़ों समस्याएं

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा मुख्यमंत्री जी, यदि गंभीरता से पड़ताल करेंगे तो ऐसी सैकड़ों समस्याएं आपके सामने आ जाएंगीं, समाधान के लिए प्रभावी नीतियों और योजनाओं की आवश्यकता है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान किया जा सके। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके अपनी महानता की कहानी सुनाना बंद कीजिए, यदि वास्तव में कुछ करना ही चाहते हैं तो उपरोक्त बिंदुओं के जरिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों का ईमानदारी से भला कीजिए।

कर्नाटक में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवा के लिए की 100 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवा वर्ग के लिए की 100 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कर्नाटक में अब दूसरे राज्य के लोग कुछ पदों पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने सभी नौकरियों के लिए स्थानीय यानी कन्नड़ होना जरूरी करार दिया है। इस खबर से कर्नाटन और खास कर बैंगलुरू में नौकरी करने वाले लोगों को झटका लग सकता है। इस बाबत सीएम सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने प्राइवेट सेक्टर में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ₹सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में 'सी और डी' ग्रेड के पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई।₹ उन्होंने आगे कहा, ₹हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ की भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए।₹

दूसरे शब्दों में सरकार के नए फैसले के मुताबिक, ग्रुप सी और डी कैटेगरी की नौकरी में 100 प्रतिशत पद कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं प्राइटेव कंपनियों से मैनेजमेंट लेवल के 50 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसी तरह नॉन-मैनेजमेंट पदों पर भी 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय लोगों को ही नौकरी मिलेगी। सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गयी।

नरेंद्र मोदी को युवाओं की परेशानी न दिखाई दे रही है और न सुनाई दे रही है

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

देश में बेरोजगारी दर 9.2% पर पहुंच गई है।

युवा परेशान हैं, नौकरी के लिए भटकने को मजबूर हैं।

लेकिन नरेंद्र मोदी को इन युवाओं की परेशानी न दिखाई दे रही है और न सुनाई दे रही है। वे तो उल्टा सारे आंकड़ों को नजरअंदाज कर झूठ फैलाने में लगे हैं।

नरेंद्र मोदी खुलेआम झूठ कह रहे हैं कि हमने 4-5 साल में रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दिया है।

जबकि सच्चाई ये है 👇

* देश के बेरोजगारों में 83% युवा हैं
* देश में दर्जनों पेपर लीक हो रहे हैं
* 30 लाख सरकारी पद खाली हैं
* 20-24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 44.49% है
* बेरोजगारी से तंग आकर हर घंटे 2 युवा आत्महत्या करते हैं
* युवा नौकरी के लिए रूस और इजराइल जाने को मजबूर हैं

नरेंद्र मोदी ने छोटे उद्योगों को बर्बाद कर देश में रोजगार के अवसर खत्म कर दिए हैं। मोदी सरकार की नीतियों ने युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है।

लेकिन नरेंद्र मोदी को युवाओं की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपने दोस्तों को अमीर बनाने में व्यस्त हैं।

सच है-

नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बेरोजगार कर, देश को तबाह और बर्बाद कर दिया है।